सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरों की भागीदारी

344. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में मजदूरों की भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार करती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रम और उद्यम है जिनमें प्रबंध बोर्ड में मजदूरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है और यह किस मात्रा में तथा किस स्तर पर दिया गया है ;

(ग) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उनके प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की भागीदारी के सिद्धांत से मुक्त रखा जाये, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस सिद्धांत को किस अवधि में पूर्णत: लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) सात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निदेशक मंडल में ट्रेड यूनियन नेताओं को नियुक्त किया है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (योजना, 1970 के अधीन, कर्मचारी/कर्मचारी निदेशकों को 22 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निदेशक मंडलों में नियुक्त किया गया है ।

(ग) दस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने प्रबंध में श्रमिक साझेदारी की योजना से छूट के लिए अनुरोध किया है ।

(घ) इनमें से नौ उपक्रमों को छूट नहीं दी गई है और उनसे उक्त योजना को लागू करने के लिए सहमत किया जा रहा है ।

(ङ) सभी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में उक्त योजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं ?

Guidelines for holding Loan Melas

345. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued by the Reserve Bank of India in respeet of holding loan melas!

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) how many loan melas have been held so far and how much money has been disbursed through these loan melas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARY): (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) has not issued any separate set of guidelines in respect of loans to be sanctioned and disbursed in credit camp. The RBI guidelines for lending to priority sector and weaker sections of society are applicable to all cases irrespective of the fact whether loans were given in a credit camp or otherwise.

(c) The present data reporting system of RBI does not yield this information since no central monitoring of credit camps held, number of benefi-ries and amount of loan sanctioned in such camps, is being done.

गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में वेतनमानों में असमानता

346. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा इसके मुख्यालय में